www.sanjanabharati.com
दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित
facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 हिंदू आस्था का मान रखने वाले जज के...
3 रवि तेजा के साथ स्क्रीन शेयर कर सकती हैं...
4 हरियाणा सरकार की ओर से जिले को जल्द...

वर्षः 10 | अंकः 48 | दिल्ली, गुरुवार, 11 दिसम्बर 2025 | पृष्ठ संख्याः 4 | मूल्यः 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में स्थान, वैश्विक पहचान हुई और मजबूत

नई दिल्ली (एजेन्सी)। दीपावली केवल भारत तक सीमित त्योहार नहीं, बल्कि विश्व पटल पर अपनी सांस्कृतिक पहचान दर्ज करा चुकी परंपरा है। बुधवार को यूनेस्को ने दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर दिया। मौजूद जानकारी के अनुसार यह निर्णय दिल्ली के लाल कि ले में आयोजित इंटरगवर्नमेंटल कमेटी की बैठक के दौरान लिया गया, जहाँ भारत इस सत्र की मेजबानी कर रहा है। बता दें कि दीपावली हिंदू परंपरा का सबसे व्यापक और भावनात्मक त्योहार माना जाता है, जिसका उत्सव भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय समुदाय द्वारा भी मनाया जाता रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि दीपावली भारतीय सभ्यता की आत्मा और हमारी सांस्कृतिक आस्थाओं का केंद्र रही है। उनका कहना था कि इस मान्यता से त्योहार की वैश्विक पहुँच और लोकप्रियता में और वृद्धि होगी।

आत्मनिर्भर भारत की ओर भारतीय रेलवे, अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की कर रहा तैयारी

नई दिल्ली (एजेन्सी)। भारतीय रेलवे ने अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार, रेलवे में हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए, प्रायोगिक आधार पर अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की अत्याधुनिक परियोजना शुरू की है। यह जानकारी रेल, सूचना एवं प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। अपने उत्तर में मंत्री ने बताया कि हाइड्रोजन ट्रेन-सेट का निर्माण पूरा हो चुका है। इस ट्रेन-सेट के लिए हाइड्रोजन की आपूर्ति हेतु जींद में एक हाइड्रोजन संयंत्र प्रस्तावित किया गया है। इस संयंत्र में विद्युत अपघटन के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है, जो हरित हाइड्रोजन उत्पादन में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्री ने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन-सेट में कई प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनमें भारत में डिजाइन और विकसित की गई ट्रेन भी शामिल है, जो आत्मनिर्भर भारत के प्रति भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

अपने नागरिकों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करना हमारा साझा कर्तव्य हैः राष्ट्रपति मुर्मु

संजना भारती/पीआईबी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बुधवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मानवाधिकार दिवस समारोह में शामिल हुईं और उपस्थित लोगों को संबोधित किया।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि मानवाधिकार दिवस हमें यह याद दिलाता है कि सर्व-जन मानवाधिकार अलग नहीं किए जा सकते हैं और वे एक न्यायपूर्ण, समतावादी और करुणामय समाज की आधारशिला हैं। सतहत्तर वर्ष पहले, विश्व एक सरल लेकिन क्रांतिकारी सत्य को व्यक्त करने के लिए एकजुट हुआ था कि प्रत्येक मनुष्य गरिमा और अधिकारों में स्वतंत्र और समान पैदा होता है। मानवाधिकारों के वैश्विक ढांचे को आकार देने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मानवीय गरिमा, समानता और न्याय पर आधारित विश्व की कल्पना की थी। राष्ट्रपति ने अंत्योदय दर्शन के अनुरूप, वंचित लोगों सहित सभी के मानवाधिकारों की गारंटी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में राष्ट्र के विकास पथ में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। तभी विकास को सही मायने में समावेशी कहा जा सकता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि मानवाधिकार हमारे संविधान की परिकल्पना में निहित हैं। मानवाधिकार सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। मानवाधिकारों में भयमुक्त जीवन जीने का अधिकार, बाधाओं के बिना शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, शोषण मुक्त होकर काम करने का अधिकार और गरिमापूर्ण तरीके से वृद्धावस्था गुजारने का अधिकार शामिल है। हमने विश्व को यह याद दिलाया है कि मानवाधिकारों को विकास से अलग नहीं किया जा सकता। साथ ही, भारत ने हमेशा इस चिरस्थायी सत्य का पालन किया हैः 'न्याय के बिना शांति नहीं और शांति के बिना न्याय नहीं।'

राष्ट्रपति ने यह जानकर प्रसन्नता व्यक्त की कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, न्यायपालिका और नागरिक समाज, सभी ने मिलकर हमारे संवैधानिक विवेक के सतर्क प्रहरी के रूप में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों के साथ-साथ महिलाओं और बच्चों से संबंधित कई मुद्दों का स्वतः संज्ञान लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष अपने स्थापना दिवस समारोह के दौरान कैदियों के मानवाधिकारों के विषय पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन चर्चाओं से उपयोगी परिणाम प्राप्त होंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण और उनका कल्याण मानवाधिकारों के प्रमुख स्तंभ हैं। उन्होंने यह जानकर प्रसन्नता व्यक्त की कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों में महिलाओं की सुरक्षा पर एक सम्मेलन का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मेलनों से प्राप्त निष्कर्ष महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राज्य और समाज के कुछ आदर्शों को साकार रूप देता है। भारत सरकार इन आदर्शों को अभूतपूर्व पैमाने पर क्रियान्वित कर रही है। पिछले एक दशक में हमने अपने राष्ट्र को एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हुए देखा है- विशेषाधिकार से सशक्तिकरण की ओर और दान से अधिकारों की ओर।

घबराइए मत, हर समस्या का होगा प्रभावी समाधानः सीएम योगी आदित्यनाथ

जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनीं 200 लोगों की समस्याएं

संजना भारती संवाददाता

गोरखपुर। मंगलवार को गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास करने के बाद बुधवार सुबह जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों से आत्मीयता से संवाद करते हुए कहा, घबराइए मत, हर समस्या का प्रभावी समाधान कराया जाएगा। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उसका समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शी निराकरण कराएं।

बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए। जनता दर्शन में महिलाओं की संख्या अधिक रही। कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे। आत्मीयता के पुट में कहां से आए हैं, क्या बात है, कहते हुए एक-एक कर सबकी समस्याएं सुनीं। भरोसा दिया कि वह सभी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराएंगे। किसी को भी परेशान होने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्रों को उन्होंने अधिकारियों को हस्तगत करते हुए निर्देश दिया कि हर समस्या का निस्तारण त्वरित, गुणवत्तापूर्ण

और संतुष्टिप्रद होना चाहिए। कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जाने की शिकायत पर उन्होंने कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। एक महिला ने मकान जला दिए जाने की शिकायत की तो मुख्यमंत्री ने जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि इलाज में धन की कमी बाधक नहीं होगी, सरकार भरपूर आर्थिक मदद देगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज में अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कराकर शासन में भेजें। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए पर्याप्त राशि दी जाएगी। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान बुधवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने तथा अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा समक्ष शीश झुकाने के बाद वह मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले। मंदिर की गोशाला में पहुंचकर गोसेवा की। गायों और गोवंश को स्नेहिल भाव से गुड़-रोटी खिलाया। गोशाला में सीएम योगी के पहुंचने पर मोर भी उनके पास आ जाते हैं। मुख्यमंत्री ने मोर को भी दुलारा और अपने हाथों से रोटी खिलाया।

कई राज्यों व विदेशों से मिले प्रशंसापत्रों ने कैलाशपुरी महाकाल बाबा के पर्यावरण अभियान को दिया नया आयाम

यूरेशिया-एफ्रो चैंबर ऑफ कॉमर्स ने नई दिल्ली कार्यक्रम में सम्मानित किया

संजना भारती संवाददाता/मदन पुरी

नई दिल्ली। देश में बढ़ते पर्यावरणीय संकट, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक असंतुलन की चुनौतियों के बीच महाकाल भैरव अखाड़े के प्रधान कैलाशपुरी जी महाराज के पर्यावरण, सामाजिक और आध्यात्मिक प्रयासों को लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है। भारत के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ ताइवान, जापान और अन्य देशों के भक्त समुदायों ने प्रशंसापत्र जारी कर बाबा के कार्यों को प्रेरक और जन-कल्याणकारी बताया है।

सोलापुर, गंगानगर, लुधियाना और कर्नाटक समेत कई क्षेत्रों से भेजे गए पत्रों में संस्थाओं ने लिखा है कि बाबा के पर्यावरण संदेशों से पेड़-रोपण कार्यक्रमों में युवाओं की सक्रियता बढ़ी। जल संरक्षण की समझ में सुधार हुआ और सामुदायिक सफाई अभियानों को नई दिशा मिली।

समाज की इन संस्थाओं ने माना कि बाबा के मार्गदर्शन ने ग्रामीण इलाकों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और एकजुटता की भावना को मजबूत किया है। ताइवान और जापान के कुछ समूहों ने अपने पत्रों में लिखा है कि जलवायु अस्थिरता और प्राकृतिक तनाव के समय उन्हें बाबा के संदेशों से मानसिक शांति और ह्यआध्यात्मिक प्रेरणाह्ल मिली। इन टिप्पणियों को समुदायों द्वारा दिए गए अनुभव बताते हुए यह भी स्पष्ट किया गया है कि वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा ऐसी आध्यात्मिक अनुभूतियों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। जडेनहल्ली स्थित श्री वरदराजेश्वर मंदिर समिति ने भी धन्यवाद-पत्र भेजा है। समिति ने बताया कि मंदिर परिसर में लाल शिवलिंग की स्थापना और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के बाद क्षेत्र में सकारात्मक वातावरण और सामुदायिक एकता बढ़ी।

राजस्थान के गांव 6 एपीडी, जिला श्रीगंगानगर से सरपंच अमनदीप कौर धन्जू और ग्रामीण प्रतिनिधियों ने बताया कि 6 अक्टूबर 2025 को गांव में आयोजित जागरण के दौरान तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई थी। उनका कहना है कि वीडियो कॉल पर बाबा के निर्देश के बाद मौसम शांत हो गया और कार्यक्रम बिना व्यवधान के संपन्न हुआ। (यह विवरण ग्रामीण समुदाय द्वारा भेजे गए पत्रों पर

यूरेशिया एफ्रो चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा बाबा कैलाशपुरी जी महाराज को सम्मानित करते हुए सदस्य। (छायाः एसबी)

आधारित है।) नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान यूरेशिया-एफ्रो चैंबर ऑफ कॉमर्स ने फिर से कैलाशपुरी महाकाल बाबा को पर्यावरण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान-पत्र और सर्टिफिकेट प्रदान किया। चैंबर ने कहा कि बाबा का प्रकृति संरक्षण अभियान वैश्विक स्तर पर जन-सहभागिता का उदाहरण बन रहा है। देश-विदेश से मिले लगातार प्रशंसापत्र बताते हैं कि कैलाशपुरी महाकाल बाबा केवल आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जल स्त्रोतों के पुनर्जीवन, प्रदूषण नियंत्रण और सामाजिक सेवा को भी उतनी ही गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। इन समुदायों का सम्मान स्पष्ट करता है कि उनका प्रभाव पर्यावरण जागरूकता से लेकर सामाजिक और आध्यात्मिक संवेदनशीलता तक व्यापक रूप से महसूस किया जा रहा है।

कोविड-19 के बाद किए गए तर्क संगत उपायों के चलते दैनिक ट्रेन सेवाओं की औसत संख्या बढ़कर 11,740 हुई

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

गोरखपुर। वर्तमान में, भारतीय रेलवे नेटवर्क पर चेयर कार वाली 164 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। इसके अलावा, वंदे भारत एक्सप्रेस और इसके वेरिएंट सहित नई ट्रेनों की शुरूआत भारतीय रेलवे में एक सतत प्रक्रिया है, जो कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैंः

उस खंड की क्षमता, मार्ग की उपलब्धता, जरुरी रोलिंग स्टॉक की उपलब्धता, रोलिंग स्टॉक के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, रेलवे ट्रैक और अन्य संपत्तियों के रखरखाव की जरुरत कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए भारतीय रेलवे (आईआर) ने 23 मार्च 2020 से सभी नियमित यात्री ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया था और केवल विशेष ट्रेनें ही चलाई जा रही थीं। भारतीय रेलवे ने आईआईटी-मुंबई की मदद से समय सारिणी का युक्तिकरण भी वैज्ञानिक तरीके से किया, जिसमें ट्रेन सेवाओं और ठहरावों का समायोजन भी शामिल था। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से यात्रियों की सुरक्षा के लिए रखरखाव कॉरिडोर ब्लॉक बनाने, ट्रेन सेवाओं की गति बढ़ाने और समय की पाबंदी में सुधार करने के लिए की गई थी। नवंबर 2021 से, एक्सप्रेस ट्रेनें युक्तिसंगत समय सारिणी और नियमित संख्या के अनुसार चलाई जा रही हैं।

भारतीय रेलवे नेटवर्क पर प्रतिदिन औसतन 11,740 ट्रेनें (नवंबर 2025) चलती हैं, जबकि कोविड-19 से पहले यह संख्या 11,283 थी। भारतीय रेलवे नेटवर्क पर प्रतिदिन औसतन 2,238 मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें (नवंबर 2025)

■ 2238 मेल और एक्सप्रेस सेवाएं, कोविड-पूर्व के 1768 ट्रेनों के दैनिक स्तर से 470 अधिक

चलती हैं, जबकि कोविड-19 से पहले यह संख्या 1,768 थी।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेनेंः लंबी और मध्यम दूरी की रात्रिकालीन यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए, वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर संस्करण को स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। ऐसे दो रैक निर्मित किए जा चुके हैं और परीक्षण/चालू करने की प्रक्रिया में हैं।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में उपलब्ध व्यापक तकनीकी प्रगति और सुरक्षा विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

कवच से सुसज्जित, 180/160 किमी प्रति घंटा की डिजाइन/ऑपरेटिंग गति के साथ उच्च वेगवृद्धि, क्रैशप्रूफ और झटके-रहित अर्ध-स्थायी कपलर और एंटी-क्लाइम्बर, ईएन मानकों के अनुरूप क्रैशप्रूफ कारबॉडी डिजाइन, ईएएन-45545 एचएल3 अग्नि सुरक्षा मानक, प्रत्येक कोच के अंत में आग को रोकने वाले दरवाजे, विद्युत कैबिनेट और शौचालयों में उन्नत एयरोसोल आधारित अग्नि पहचान और शमन प्रणाली, ऊर्जा दक्षता के लिए रीजेनरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली, स्वदेशी रूप से विकसित यूवी-सी लैंप आधारित कीटाणुशोधन प्रणालियों से सुसज्जित एयर कंडीशनिंग इकाइयाँ, केंद्रीय रूप से नियंत्रित स्वचालित प्लग दरवाजे और पूरी तरह से सीलबंद चौड़े गलियारे, सभी कोचों में सीसीटीवी कैमरे, आपातकालीन स्थिति में यात्री और ट्रेन प्रबंधक/लोको पायलट के बीच संपर्क के लिए आपातकालीन टॉक-बैक यूनिट

दिव्यांगजन यात्रियों के लिए प्रत्येक छोर पर स्थित ड्राइविंग कोचों में विशेष शौचालय, एयर कंडीशनिंग, सैलून लाइटिंग आदि जैसी यात्री सुविधाओं की बेहतर निगरानी के लिए केंद्रीकृत कोच निगरानी प्रणाली, ऊपरी बर्थों पर चढ़ने में आसानी के लिए एर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन की गई सीढ़ी, यह जानकारी केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में प्रश्नों के लिखित उत्तर में दी।

ठंड मे बेबस लोगों के लिए सहारा बनी पंचकूला पुलिस, 1000 से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई राहत सामग्री

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजेश कुमार

पंचकूला। पंचकूला पुलिस ने मानवीय संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण पेश करते हुए ठिठुरन भरी सर्द रातों में उन लोगों तक मदद पहुंचाई है, जो अक्सर समाज की भीड़ में अनदेखे रह जाते हैं। जिले की सभी क्राइम यूनिट्स ने संयुक्त रूप 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक कुल 1032 जरूरतमंद लोगों को कंबल, ऊनी कपड़े, जैकेट खाने-पीने की सामग्री वितरित की।

पुलिस की टीमें देर रात गश्त के दौरान सड़कों, चौक-चौराहों, बस स्टैंड, मार्केट एरिया, खाली प्लॉट्स और फुटपाथों पर सो रहे लोगों के पास पहुंची। कई जगह पुलिसकर्मी खुद गाड़ी रोककर उन बुजुर्गों, मजदूरों, महिलाओं और बच्चों से बातचीत करते दिखे, जो ठंड की मार झेलते हुए किसी तरह रात काट रहे थे। पुलिसकर्मियों ने अपने हाथों से उन्हें कंबल ओढ़ाए, गर्म कपड़े पहनाए और खाने का सामान थमाया।

एटीवी स्टाफ ने जरूरतमंदों के लिए भंडारा लगाकर खाने की व्यवस्था भी की। ठंड और भूख से जूझ रहे इन लोगों के चेहरे पर संतोष और राहत के भाव देखकर पुलिसकर्मी भी संतुष्ट दिखे। डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि हमारी क्राइम

यूनिट्स हर रोज जरुरतमंदो तक पहुंच रही है यह अभियान केवल वस्त्र और भोजन वितरण भर नहीं है, बल्कि समाज में इंसानियत और करुणा का संदेश फैलाने का प्रयास है। उनका कहना है कि पंचकूला पुलिस अपराधियों को पकड़ने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ उन लोगों की भी जिम्मेदारी समझती है, जिनके पास कोई सहारा नहीं। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी नागरिक भूख, ठंड या अभाव के कारण परेशान न रहे।

साथ ही यह भी कहा कि यदि समाज का हर सक्षम व्यक्ति यदि जरूरतमंद की मदद करने की ठान ले, तो कोई भी इंसान रात ठंड में गुजारने या भूखा रहने के लिए मजबूर नहीं होगा। अधिकारियों ने जिला निवासियों से अपील की है कि वे ऐसे नेक कार्यों में आगे आएं, पुराने कपड़े, कंबल, खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करें और अपने आसपास मौजूद लोगों का सहारा बनें।

जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा प्रदेश की औद्योगिक प्रगति में नया मील का पत्थर साबित होगाः मुख्यमंत्री

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे के दौरान निवेशकों का मिला भरपूर उत्साह प्रदेश की औद्योगिक प्रगति में नया मील का पत्थर साबित होगा और इससे पंजाब को सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभारने में और तेजी आएगी। जापान और दक्षिण कोरिया के दौरों के अपने अनुभव साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पंजाब को दुनिया भर में उभरते हुए औद्योगिक केंद्र के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करना और औद्योगिक विकास को गति देकर युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह ऐतिहासिक दौरा औद्योगिक विकास को तेज रफ्तार देने और उसे आवश्यक बल प्रदान करने में सहायक होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बैठक के दौरान जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर ओगावा काजूनोरी ने पंजाब के औद्योगिक और स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्टों की संभावनाओं की खोज में रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि वे जापानी कंपनियों के माध्यम से संभावित वित्तीय अवसरों पर तकनीकी विचार-विमर्श जारी रखने के लिए सहमत हुए हैं।

सम्पादकीय

चुनाव सुधार पर चर्चा

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी 'वोट चोरी' के कृत्य को अंजाम देकर सबसे बड़ा देशविरोधी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा और संघ 'द आइडिया ऑफ इंडिया' यानी भारत की अवधारणा को नष्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी पहले भी वोट चोरी के इल्जाम लगाते हुए कई सबूत भी पेश कर चुके हैं, जिनमें महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। नेता प्रतिपक्ष के इन आरोपों पर भाजपा ने हमेशा चुनाव आयोग का बचाव किया है और खुद चुनाव आयोग ने भी इन आरोपों का तार्किक जवाब देने की जगह इन पर फेक का ठप्पा लगाकर खारिज कर दिया है। लेकिन लोकतंत्र इतने उथलेपन के साथ नहीं चल सकता कि विपक्ष के आरोपों को गलत कहकर अपनी जिम्मेदारी से बरी हुआ जाए। सरकार और चुनाव आयोग दोनों को इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर मतदाता सूची में तथाकथित शुद्धिकरण की जरूरत अभी क्यों पड़ी है। बिहार के बाद चुनाव आयोग ने देश के 12 और राज्यों में मतदाता सूची का एसआईआर करवाया है, आज यानी 11 तारीख को एसआईआर के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। पहले यह मियाद 4 दिसंबर तक थी, लेकिन जब चुनाव आयोग को खुद यह समझ आया कि इतनी जल्दी करोड़ों मतदाताओं की सूची फिर से तैयार नहीं हो सकती तो तारीख आगे बढ़ाई गई। हालांकि विपक्ष पहले ही इस जल्दबाजी पर सवाल उठा रहा था। एसआईआर का मामला अदालत में भी है, लेकिन चुनाव आयोग ने न बिहार चुनाव के वक्तविपक्ष की आपत्तियों और लोगों की तकलीफों पर ध्यान दिया न अब दे रहा है। इस बीच एसआईआर के काम में लगे कई बीएलओज की अकाल मौत या गंभीर रूप से बीमार होने की खबरें आ चुकी हैं। मगर चुनाव आयोग ने यह माना ही नहीं कि बीएलओज पर काम का या कुछ खास समुदायों के वोट काटने का दबाव है। एसआईआर से जुड़े ऐसे कई सवालों पर विपक्ष सदन में भी चर्चा चाहता था ताकि देश को इस बारे में सरकार का आधिकारिक नजरिया पता चले। पिछले मानसून सत्र में विपक्ष की इस मांग को सरकार ने टाल दिया था, लेकिन शीतकालीन सत्र में सरकार अपनी जिद पर टिक नहीं पाई। एसआईआर तो नहीं लेकिन चुनाव सुधार के नाम पर चर्चा के लिए सरकार राजी हुई। अब इसमें विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं, उनके बेतुके जवाब भाजपा दे रही है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान न केवल एसआईआर की बात की, बल्कि भाजपा और संघ के लोकतंत्र से खिलवाड़ पर हमला भी किया। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद इनके 'प्रोजेक्ट' का अगला हिस्सा भारत के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने का था। राहुल ने दावा किया, 'आरएसएस ने एक-एक करके संस्थाओं पर कब्जा शुरू कर दिया। सब लोग जानते हैं कि विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति कैसे होती है। निर्वाचन आयोग, विश्वविद्यालयों, खुफिया एजेंसियों, जांच एजेंसियों और आयकर विभाग जैसी संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है।' राहुल गांधी ने कहा कि देश 1.5 अरब लोगों का ताना-बाना है जो वोट के माध्यम से बुना हुआ है। अगर वोट का ही मतलब नहीं रह जाएगा तो लोकसभा, विधानसभा या पंचायत, किसी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की चयन प्रक्रिया से अब मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयु (नियुक्ति, सेवा-शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' के तहत तीन सदस्यीय चयन समिति में अब प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इस पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस सरकार ने दिसंबर 2023 में कानून बदल दिया ताकि अपनी मर्जी से नियुक्ति हो। किसी चुनाव आयुक्त को उसके फैसलों के लिए दंडित नहीं किया जा सके। राहुल ने पूछा कि आखिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने दावा किया कि इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। राहुल की तरह कुछ और विपक्षी सांसदों ने भी यही सवाल सदन में किया। जिसके जवाब में अब रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हम सभी न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। लेकिन न्यायपालिका को हर चीज़ में शामिल करना क्या सही है? क्या ये 'सेपरेशन ऑफ पावर' के खिलाफ तो नहीं है? और क्या हम अपनी कमजोरी को तो नहीं दिखा रहे हैं? हम अपने से कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक सीजेआई नहीं आएंगे। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।' उन्होंने बेतुकी बात कही कि भारत के प्रधानमंत्री के पास न्यूक्लियर बटन होता है कि नहीं? 'देश की जनता प्रधानमंत्री, देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और रणनीतियों में विश्वास करती है। भारत की चुनी हुई सरकार इतना कर सकती है लेकिन एक अच्छा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं चुन सकती। ये कौन-सी बात कही जा रही है?' इस जवाब से जाहिर हो रहा है कि भाजपा एक बार फिर मूल सवाल को भटका रही है।

जयंती

सुब्रह्मण्य भारती

जन्म: 11 दिसंबर, 1882-मृत्यु: 11 सितंबर, 1921) भारत के महान कवियों में से एक थे, जिन्होंने तमिल भाषा में काव्य रचनाएँ की। इन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। भारती एक जुझारू शिक्षक, देशप्रेमी और महान कवि थे। आपकी देश प्रेम की कविताएँ इतनी श्रेष्ठ हैं कि आपको भारती उपनाम से ही पुकारा जाने लगा। तमिल भाषा के महाकवि सुब्रमण्य भारती ऐसे साहित्यकार थे, जो सक्रिय रूप से 'स्वतंत्रता आंदोलन' में शामिल रहे, जबकि उनकी रचनाओं से प्रेरित होकर दक्षिण भारत में आम लोग आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। ये ऐसे महान कवियों में से एक थे, जिनकी पकड़ हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं पर थी, पर तमिल उनके लिए सबसे प्रिय और मीठी भाषा थी। उनका 'गद्य' और 'पद्य' दोनों विधाओं पर समान अधिकार था।

पुण्यतिथि

एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी

जन्म-16 सितंबर, 1916 मद्रास; मृत्यु-11 दिसंबर, 2004 चेन्नई, को कर्नाटक संगीत का पर्याय माना जाता है और भारत की वह ऐसी पहली गायिका थीं, जिन्हें सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके गाये हुए गाने, खासकर भजन आज भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें संगीत की रानी बताया तो वहीं स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने उन्हें 'तपस्विनी' कहा।

कल मिलेंगे

एक पार्टी में नेहा ने अपनी सहेली अंकिता से कहा-
देखो वो लड़का कितना बोलता है,
लगातार बोलता ही जा रहा है
इस पर नेहा ने कहा-एक महीने बाद उसकी
बोलती बंद हो जाएगी
अंकिता-वो कैसे?
नेहा-अगले महीने मैं उससे शादी जो करने जा रही हूं.....

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।

RNI No. : DELHI/2016/70240

Phone No.: 9871221635

E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com

(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

हिंदू आस्था का मान रखने वाले जज के खिलाफ पूरे विपक्ष का एकजुट होना चिंताजनक मिसाल है

वैसे तो सनातन धर्म के विरुद्ध डीएमके के कई नेताओं के वक्तव्य पहले ही सामाजिक समरसता को कमजोर करते रहे हैं। अब दीपथूण पर दीप जलाने के खिलाफ प्रशासनिक दमन और फिर न्यायाधीश पर निशाना साधना इस बात का प्रमाण है कि यह विवाद मूलतः विधिक नहीं, बल्कि वैचारिक और राजनीतिक है। इसमें आस्था को बार-बार चोट पहुँचाई गई है और उन भक्तों को अपराधी जैसा व्यवहार झेलना पड़ा है जिन्होंने केवल अपनी परंपरा निभानी चाही

-नीरज कुमार दुबे

हिंदू-बहुल भारत में आखिर यह स्थिति क्यों पैदा हो गई है कि किसी हिंदू को अपने ही प्राचीन धर्मस्थल पर दीपक जलाने या पूजा करने के लिए अदालत से अनुमति लेनी पड़े? यह स्थिति आखिर क्यों पैदा हो गयी है कि न्यायालय पूजा की अनुमति दे दे तो सरकार उस अनुमति के क्रियान्वयन को ही रोक दे? यह स्थिति क्यों बन गयी है कि अदालत अनुमति दे दे तो कुछ राजनीतिक दल उस न्यायाधीश को ही पद से हटाने की मांग करने लगें जिसने हिंदुओं को अपने धर्म स्थल पर पूजा करने की अनुमति दी? क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक दृश्य है? सवाल उठता है कि तुष्टिकरण की राजनीति की आड़ में हिंदू आस्था को बार-बार क्यों चोट पहुँचायी जाती है? क्या बहुसंख्यक धर्म की परंपराएँ केवल इसलिए संदेह के घेरे में हैं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक की राजनीति को धर्म और इतिहास से ऊपर रख चुके हैं? और क्या अब न्यायपालिका तक को इस आधार पर निशाना बनाया जाएगा कि उसका निर्णय किसी समुदाय को राजनीतिक रूप से असुविधाजनक लगा?

इन मूलभूत प्रश्नों के बीच तिरुप्परनकुंद्रम का दीपथूण विवाद केवल एक धार्मिक अनुष्ठान का मामला नहीं रह गया है; यह प्रशासनिक निष्पक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हो रही राजनीति की वास्तविकता का आईना बन चुका है। हम आपको बता दें कि मदुरै के तिरुप्परनकुंद्रम में अरुलमिघु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर और उससे सटे दीपथूण (पत्थर के दीप-स्तंभ) पर दीप प्रज्वलन को लेकर उठा विवाद लगातार कानूनी और राजनीतिक टकराव का रूप लेता जा रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा दीपथूण पर दीप जलाने की अनुमति देने के बाद राज्य सरकार ने न केवल इस आदेश को चुनौती दी बल्कि जिला प्रशासन ने भी पर्वत की तलहटी पर ही श्रद्धालुओं को रोक दिया। इस घटना ने न्यायपालिका और राज्य सरकार के बीच तनाव को सार्वजनिक रूप से उद्घाटित कर दिया। हम आपको बता दें कि 1 दिसंबर को न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने हिंदू तमिलर कच्ची के संस्थापक राम रविकुमार की याचिका पर आदेश देते हुए भक्तों को तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथूण पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। लेकिन 3 दिसंबर के कार्तिगई दीपम उत्सव के दिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया जिसके बाद रविकुमार ने अवमानना याचिका दायर की। उसी दिन न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने दस भक्तों को दीपथूण तक जाने और वहाँ दीप प्रज्वलित करने की अनुमति दी तथा उनकी सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ कवर प्रदान करने का निर्देश दिया। इसके बावजूद पुलिस ने समूह को रोक दिया और राज्य सरकार ने अवमानना कार्यवाही से बचने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

हम आपको बता दें कि इस मामले की जड़ें लगभग सौ वर्ष पुरानी हैं। तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी, जो भगवान मुरुगन के छह प्रमुख पवित्र स्थलों में से एक है, वहां पर स्थित मंदिर और एक दरगाह के बीच 1920 से ही स्वामित्व और धार्मिक अधिकारों को लेकर विवाद रहा है। उस समय सिविल कोर्ट और बाद में प्रिवी काउंसिल ने पहाड़ी को मंदिर सम्पत्ति घोषित किया था। किंतु दीप प्रज्वलन की परंपरा को लेकर न्यायालय ने 1996 में यह कहा था कि पारंपरिक स्थान मंदिर परिसर का उचिपिल्लैयार कोविल मंडपम है; हालांकि भविष्य में किसी वैकल्पिक स्थान पर दीप प्रज्वलन की अनुमति HR&CE विभाग द्वारा दी जा सकती है, बशर्ते वह दरगाह से दूर हो।

इसके बाद भी दीपथूण को पारंपरिक स्थल बताकर कई याचिकाएँ दायर हुईं, जिन पर 2014 और 2017 में उच्च न्यायालय ने यह दोहराया था कि मंदिर प्रबंधन ही धार्मिक परंपराओं और स्थलों का निर्धारण करेगा। लेकिन इस वर्ष पुनः इस विवाद ने जोर पकड़ा और राजनीतिक रंग ले लिया। राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील दायर कर दी है। वहीं 5 दिसंबर को खंडपीठ ने मंदिर प्रबंधन का पक्ष रखते हुए यह चेतावनी दी कि न्यायपालिका का अपमान करने वाली टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद 9 दिसंबर को अदालत ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव और एडीजीपी (कानून-व्यवस्था) को 17 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का आदेश दिया, क्योंकि प्रशासन ने न्यायालय के पूर्व आदेशों का पालन नहीं किया।

दूसरी ओर, यह विवाद इसी बीच संसद तक पहुँच गया है। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, एनसीपी (एसपी) और AIMIM से संबद्ध 107 विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति स्वामीनाथन को हटाने का प्रस्ताव सौंपा। आरोप लगाया गया कि न्यायाधीश ने एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर निर्णय दिए और निष्पक्षता व धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्नचिह्न लगा है। देखा जाये तो विपक्ष का यह कदम अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक टकराव बन चुका है, क्योंकि इसे न्यायपालिका पर सीधे प्रहार के रूप में देखा जा रहा है। जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने न्यायाधीश के निर्णय से असहमति को आधार बनाकर उन्हें हटाने का प्रस्ताव दिया, वह भारतीय लोकतंत्र में अभूतपूर्व और चिंताजनक मिसाल है।

सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी का इतिहास केवल मंदिर-प्रशासन से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यह हिंदू आस्था का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र है जहाँ सदियों से भक्तों की उपस्थिति रही है। 1920 के सिविल डिक्री और प्रिवी काउंसिल के निर्णय ने स्पष्ट कहा था कि पहाड़ी मंदिर की संपत्ति है तथा दरगाह उससे केवल कुछ सीमित हिस्सों में सम्बद्ध है। यह तथ्य अपने आप में बताता है कि दीपथूण पर दीप जलाना मंदिर-परिसर के भीतर ही धार्मिक अनुष्ठान का एक स्वाभाविक हिस्सा है।

फिर भी, पिछले तीन दशकों में दीपथूण को लेकर विवाद गहराता गया और प्रशासन ने अक्सर सुरक्षा या साम्प्रदायिक संवेदनशीलता का हवाला देकर हिंदू परंपराओं को सीमित किया। यह वही मानसिकता है जो डीएमके और उसके सहयोगियों की राजनीति में बार-बार दिखाई देती है, जहाँ बहुसंख्यक आस्था को दबाकर तुष्टिकरण को राजनीतिक लाभ का साधन बना दिया जाता है। यह संयोग नहीं है कि वही दल, जिसके नेताओं ने अनेक बार सनातन धर्म को नष्ट करने योग्य कहा, वही आज दीपथूण में दीप जलाने का विरोध कर रहा है।

यहाँ प्रश्न केवल परंपरा का नहीं, बल्कि अधिकारों का है। जब उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश मौजूद था कि भक्त दीपथूण पर दीप जला सकते हैं, तब राज्य सरकार द्वारा उसे लागू न करना न केवल न्यायालय की अवमानना है बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता का खुला हनन भी है। जिस प्रकार अदालत ने पुलिस और प्रशासन को फटकारते हुए कहा कि न्यायपालिका का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, वह बताता है कि सरकार किस हद तक अपनी सीमाएँ भूल चुकी है। लेकिन इससे भी खतरनाक कदम था 107 विपक्षी सांसदों द्वारा न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव। यह केवल असहमति का मुद्दा नहीं, बल्कि न्यायपालिका को धमकाने का सीधा प्रयास है। अगर किसी निर्णय से असहमति हो तो अपील का मार्ग उपलब्ध है; परन्तु न्यायाधीश की नीयत पर प्रश्नचिह्न लगाना और उन्हें राजनीतिक विचारधारा से जोड़कर हटाने का प्रयास करना लोकतांत्रिक संस्थाओं को अस्थिर करने जैसा है। यह न्यायपालिका को संदेश देता है कि धार्मिक मामलों पर निर्णय देते समय राजनीतिक दबाव को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि किसी भी स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था के लिए विषाक्त है।

वैसे तो सनातन धर्म के विरुद्ध डीएमके के कई नेताओं के वक्तव्य पहले ही सामाजिक समरसता को कमजोर करते रहे हैं। अब दीपथूण पर दीप जलाने के खिलाफ प्रशासनिक दमन और फिर न्यायाधीश पर निशाना साधना इस बात का प्रमाण है कि यह विवाद मूलतः विधिक नहीं, बल्कि वैचारिक और राजनीतिक है। इसमें आस्था को बार-बार चोट पहुँचाई गई है और उन भक्तों को अपराधी जैसा व्यवहार झेलना पड़ा है जिन्होंने केवल अपनी परंपरा निभानी चाही।

बहरहाल, यह विवाद एक व्यापक प्रश्न खड़ा करता है कि क्या भारत में बहुसंख्यक आस्था को केवल इसलिए सीमित किया जा सकता है कि कुछ राजनीतिक दल अपने वोट-बैंक को नाराज नहीं करना चाहते? क्या न्यायाधीश केवल इसलिए निशाने पर होंगे कि उन्होंने संविधान और न्यायिक मयार्दा के आधार पर निर्णय दिया, न कि राजनीतिक सुविधा के अनुसार? विपक्ष को समझना होगा कि तिरुप्परनकुंद्रम की पहाड़ी केवल एक पहाड़ी नहीं, वह आस्था का स्रोत है। वहाँ दीप जलाना किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि एक परंपरा का निर्वाह है। इसे रोकना और फिर इसे अनुमति देने वाले न्यायाधीश को निशाना बनाना, दोनों ही लोकतांत्रिक मयार्दाओं के विपरीत हैं। विपक्ष को चाहिए कि सनातन पर प्रहार और न्यायपालिका पर दबाव के जरिये भारत की अवधारणा को कमजोर नहीं करे।

गोवा हादसा: झुलसती संवेदनाएं और नाकाम होती व्यवस्था

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर हम हादसों को नियति क्यों मान लेते हैं? हर घटना के बाद नेताओं के बयान आते हैं-दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन क्या कभी हमने दोषियों को सजा होते देखा है? कभी किसी अधिकारी को बर्खास्त होते देखा है? क्या किसी क्लब या होटल की अनुमति स्थायी रूप से रद्द की गई? जवाब अधिकतर नहीं है

-ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

एक बार फिर एक भीषण आग ने 25 मासूम जिंदगियों को छीन लिया। गोवा के नाइट क्लब में हुई यह त्रासदी केवल आगजनी नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की जड़ता, गैर-जिम्मेदारी और नैतिक पतन की ज्वलंत मिसाल है। गोवा का जो नाइट क्लब आग की चपेट में आया, वह नियमों की अनदेखी करके तो चलाया ही जा रहा था, उसमें आग से बचाव के उपाय भी नहीं किए गए थे। रही-सही कसर इससे पूरी हो गई कि नाइट क्लब में आने और जाने का रास्ता बेहद संकरा था। आग की चपेट में आने वालों की संख्या इसलिए अधिक बढ़ गई, क्योंकि बचने के लिए उन्होंने जिस रास्ते को सुरक्षित समझा, वहां पहले से ही लोग फंसे हुए थे। इस तरह से आनंद और उत्सव का स्थल अचानक जीवन समाधि में बदल गया, वह अनेक सवाल हमारे सामने खड़े करता है, क्या हम सीखने की क्षमता खो चुके हैं? क्यों हर हादसे के बाद जांच समितियां बनती हैं, मुआवजा घोषित होता है, कुछ दिन हंगामा होता है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है? पूर्व में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, सूरत और अनेक शहरों में समान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। होटल, मॉल, थिएटर, अस्पताल, फैक्ट्री, कोचिंग सेंटर-लापरवाही की आग में झूलसनों वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन हमारी संवेदनशीलता का स्तर छोटा होता जा रहा है। आगजनी की घटनाओं का सिलसिला तो लगातार है, परंतु सुरक्षा मानकों के प्रति हमारी उदासीनता और घोर लापरवाही भी उतनी ही स्थायी है। यह बात स्पष्ट है कि हादसे किसी तकनीकी गलती का परिणाम भर नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और राजनीतिक मिलीभगत की देन भी हैं।

गोवा अपनी पहचान पर्यटन से बनाता है। नाइट लाइफ, समुद्री तटों का आनंद, मनोरंजन गतिविधियां और विदेशी पर्यटक इसका स्वाभाविक आकर्षण हैं। ऐसे प्रदेश में इस प्रकार का हादसा केवल मानवीय त्रासदी नहीं, बल्कि छवि और अर्थव्यवस्था का गहरा नुकसान भी है। भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री पहले ही प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा को लेकर चुनौतियों से जूझ रही है। यह घटना विश्व के सामने एक सवाल बनकर खड़ी है-क्या भारत सुरक्षित पर्यटन देश है? क्या यहां गैर-जिम्मेदाराना ढांचे और भ्रष्ट तंत्र के बीच किसी का जीवन सुरक्षित रखा जा सकता है? इस प्रकार के हादसों में दो बड़े चरित्र सामने आते हैं-सरकार की सुस्ती और आयोजकों की लालचपूर्ण मानसिकता। अधिकांश नाइट क्लब, बार, पार्क या मनोरंजन स्थल ऐसे होते हैं जहां प्रवेश शुल्क, अवैध संचालन और आर्थिक लाभ का बड़ा खेल चलता है। इमारतों की मंजूरी, फायर सुरक्षा की अनुमति, बिजली के तारों का रखरखाव, निकास मार्ग-ये सभी चीजें फाइलों में तो दर्ज होती हैं, लेकिन जमीन पर गायब रहती हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की सजगता की जगह संबंध और सुविधा शुल्क काम करता है। निरीक्षण के नाम पर औपचारिकता ढहती है और बीते हुए हादसे केवल याद बनकर रह जाते हैं।

नाइट क्लब तक पहुंचने का रास्ता इतना संकरा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को 400 मीटर दूर खड़ा होना पड़ा। सजावट के लिए ताड़ के सूखे पत्तों का इस्तेमाल किया गया था, जिसने आग और भड़का दी। भीड़भाड़ वाली जगहों पर एंट्री से ज्यादा महत्वपूर्ण इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इस क्लब में लगता है कि इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे कई लोग भटक कर किचन में पहुंच गए, जहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। यह नाइटक्लब बिना मंजूरी के चल रहा था। लोकल अथॉरिटी के मुताबिक, निर्माण अवैध था।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर हम हादसों को नियति क्यों मान लेते हैं? हर घटना के बाद नेताओं के बयान आते हैं-दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन क्या कभी हमने दोषियों को सजा होते देखा है? कभी किसी अधिकारी को बर्खास्त होते देखा है? क्या किसी क्लब या होटल की अनुमति स्थायी रूप से रद्द की गई? जवाब अधिकतर नहीं है। यही वह सत्य है जो बताता है कि हमारा समाज हादसे को दुख तो मानता है पर समस्या नहीं मानता। अजीब विडंबना यह है कि हादसे के शिकार गरीब या आम नागरिक होते हैं, लेकिन इस त्रासदी से गुजरी व्यवस्थाओं को कोई चोट नहीं लगती। वे फिर उठते हैं, नए सजावटी बोर्ड लगा लेते हैं और जनता को फिर से आकर्षित कर लेते हैं। व्यवस्था में भ्रष्टाचार और मानव-मूल्यों का ह्रास दोनों मिलकर ऐसी घटनाओं को जन्म देते हैं। यह केवल प्रशासनिक नाकामी नहीं, बल्कि सामूहिक नैतिक ह्रास भी है। आयोजक केवल लाभ देखते हैं; प्रशासन केवल कागजों पर निशान देखता है; समाज घटना को क्षणिक दुख समझकर भूल जाता है।

वैश्विक स्तर पर देखें तो किसी भी विकसित या उत्तरदायी समाज में जन-स्थलों पर सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। नियमित निरीक्षण, कठोर दंड, मानकों का अनिवार्य पालन और पारदर्शिता बुनियादी तत्व हैं। भारत में ये मानक केवल कानूनी पुस्तकों में रहते हैं। सवाल यह नहीं कि हादसे क्यों होते हैं, सवाल यह है कि सीख क्यों नहीं ली जाती। गोवा का यह हादसा एक चेतावनी है, अकेले गोवा के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए। हम विकास, पर्यटन और आधुनिक जीवनशैली की बात करते हैं, लेकिन सुरक्षा, नियंत्रण और मानवीय संवेदनशीलता को हाशिए पर छोड़ देते हैं। यह घटना बताती है कि यदि व्यवस्था की लापरवाही और लालच के बीच नागरिक की सुरक्षा कुचलती रही तो हम आधुनिक ढांचे बनाकर भी असुरक्षित रहेंगे। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके नागरिकों की सुरक्षा पर टिकी होती है, न कि केवल चमक-दमक पर।

गोवा घटना ने सरकार की छवि को ध्वस्त किया है। पर्यटन उद्योग की नींव हिलाई है और नागरिक विश्वास को चोट पहुंचाई है। गोवा के जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा 16 प्रतिशत से ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल की तुलना में इस साल जनवरी से सितंबर के बीच 6.23 प्रतिशत ज्यादा टूरिस्ट गोवा पहुंचे। ऐसे में यह घटना राज्य की अच्छी छवि पेश नहीं करती, जहां पहले ही टैक्सी चालकों की मनमानी और पर्यटकों के साथ अभद्रता की कुछ समस्या रही है।यदि घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकनी है तो कुछ कठोर कदम उठाने होंगे, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई, वास्तविक निरीक्षण प्रणाली, भ्रष्टाचार पर अंकुश और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर दंड। परंतु दुख यह है कि हमारा इतिहास बताता है, हम कठोर कदम उठाने से बचते हैं। आज इस त्रासदी के बाद शोक जताना पर्याप्त नहीं है। इस पर गंभीर चिंतन जरूरी है। हम केवल जिम्मेदारी टाल देने की प्रवृत्ति में नहीं जी सकते। हर हादसा हमें यही याद दिलाता है कि सुरक्षा संस्कृति, जिम्मेदार शासन और नैतिक व्यवसायिक आचरण के बिना कोई भी समाज सुरक्षित नहीं हो सकता। यह घटना केवल 25 लोगों की मौत नहीं, बल्कि चेतावनी है कि यदि हमने नहीं सीखा, तो अगली त्रासदी निकट ही खड़ी है।

हमारे नीति-नियंताओं को यह समझना होगा कि इस तरह की घटनाएं केवल जान-माल को ही क्षति नहीं पहुंचातीं, बल्कि देश की बदनामी भी कराती हैं। इस तरह की घटनाएं यही रेखांकित करती हैं कि नया और विकसित बनने के आकांक्षी भारत में नियम-कानूनों की हर स्तर पर उपेक्षा होती है और इस देश में जिम्मेदारी के साथ कोई काम मुश्किल से ही किया जाता है। मानकों और सुरक्षा उपायों की रेगुलर चेकिंग अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है। बिना लाइसेंस चल रहे क्लब, होटल या रेस्तरां को बंद कराने के साथ यह जानना भी जरूरी है कि आखिर ये खुल कैसे जाते हैं और फिर कैसे धड़ल्ले से चलते रहते हैं। हमें यह मानना होगा कि जीवन की कीमत केवल शब्दों में नहीं, व्यवस्था में भी झलकनी चाहिए। जब तक हमारी नीतियों में कठोरता नहीं आएगी, जब तक भ्रष्टाचार की जड़ें नहीं काटी जाएंगी और जब तक नागरिक-केंद्रित शासन स्थापित नहीं होगा, तब तक मनोरंजन के नाम पर मौतें होती रहेंगी। गोवा का नाइट क्लब हादसा केवल आग नहीं-हमारे विवेक, शासन और मानवता की विफलता है। अब यह हमारे हाथ में है कि हम इसे भूलें या इसे परिवर्तन की शुरूआत बनाएं।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

खेल/विदेश/कारोबार/फिल्म

ट्रम्प ने फिर दोहराया दावा: भारत-पाकिस्तान संघर्ष मैंने रोका, जबकि भारत करता रहा इनकार

(एजेन्सी)।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक बार फिर भारत-पाकिस्तान तनाव को लेकर अपने पुराने दावे को दोहराते दिखाई दिए। मौजूद जानकारी के अनुसार उन्होंने पेन्सिलवेनिया के माउंट पोकोनो में आयोजित एक चुनावी सभा में कहा कि इस वर्ष मई में भारत और पाकिस्तान टकराव की स्थिति में थे और उन्होंने इस संघर्ष को खत्म कराया। बता दें कि ट्रम्प इसी दावे को अब तक लगभग 70 बार दोहरा चुके हैं, जबकि भारत ने हर बार स्पष्ट किया है कि दोनों देशों के बीच किसी भी प्रकार की मध्यस्थता या थर्ड पार्टी हस्तक्षेप की बात नहीं होती है।

गौरतलब है कि 7 मई को भारत ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान के दौरान चार दिनों तक ड्रोन और मिसाइल हमलों का सिलसिला चला और 10 मई को दोनों देशों के बीच युद्धविराम जैसा समझौता हुआ था। भारत का रुख लगातार यह रहा है कि सुरक्षा, सीमा नियंत्रण और दहशतगर्दी से निपटने के मुद्दे द्विपक्षीय स्वरूप में ही सुलझाए जाते हैं और बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है।

इसी भाषण में ट्रम्प ने यह भी दावा किया कि कंबोडिया और थाईलैंड फिर लड़ाई की स्थिति में हैं और वह कल फोन कर इसे भी रोक देंगे। ट्रम्प के शब्दों में, वे इसे शक्ति के माध्यम से शांति स्थापित करने का तरीका बताते हैं, जो उनके अनुसार पहले भी कई देशों के बीच तनाव कम करने में कारगर रहा है। इमिग्रेशन पर बोलते हुए ट्रम्प ने कहा कि 50 साल बाद पहली बार अमेरिका में रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, जिससे अमेरिकी नागरिकों के लिए नौकरियां और वेतन में सुधार हुआ है, न कि अवैध प्रवासियों के लिए। मौजूद जानकारी के अनुसार उन्होंने तथाकथित थर्ड वर्ल्ड माइग्रेशन पर स्थायी रोक की भी घोषणा दोहराई और कुछ देशों के प्रवासियों को आर्थिक, सुरक्षा और सामाजिक खतरे का कारण बताया। इसी संदर्भ में उन्होंने अफगानिस्तान, हैती, सोमालिया और अन्य देशों को खतरनाक क्षेत्र कहते हुए अपमानजनक भाषा में उल्लेख किया, जिस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले भी आलोचनाएँ हो चुकी हैं।

बता दें कि इसी माह अमेरिकी प्रशासन ने 19 उच्चझजोखिम देशों के लिए नई सुरक्षा स्क्रीनिंग गाइडलाइन जारी की है, जिनमें अफगानिस्तान, चाड, कांगो, क्यूबा, सोमालिया, सूडान, ईरान, लीबिया, वेनेजुएला और यमन शामिल हैं। ट्रम्प द्वारा जारी पूर्व राष्ट्रपति आदेश के तहत इन देशों से आने वाले प्रवासियों पर प्रतिबंध और सख़्त जांच पहले से लागू है। इन प्रावधानों का आधार यह बताया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद-नियंत्रण और जन-सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि कई मानवाधिकार संगठनों ने इस नीति को पक्षपाती और असंतुलित बताया है।

सेंसेक्स, निफ्टी में लगातार दो सत्र से जारी भारी गिरावट के बाद तेजी

(एजेन्सी)।
सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार दो सत्र से जारी भारी गिरावट के बाद बुधवार को शुरूआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई। निचले स्तरों पर खरीदारी से बाजार में तेजी आई। 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स शुरूआती कारोबार में 259.31 अंक या 0.31 प्रतिशत चढ़कर 84,925.59 अंक पर पहुंच गया।

वहीं 50 शेयर वाला एनएसई निफ्टी 64.65 अंक या 0.25 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,904.30 अंक पर रहा। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से अदाणी पोट्र्स, बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, ट्रेंट, आईटीसी, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर लाभ में रहे। वहीं इटर्नल, सन फार्मास्यूटिकल्स, टाइटन, भारती एयरटेल और इन्फोसिस के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। एशियाई बाजारों में चीन का एसएसई कम्पोजिट, हांगकांग का हैंग सेंग और जापान का निक्की 225 नकारात्मक दायरे में रहे जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लाभ मे रहा। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में मंगलवार को रात भर के कारोबार में व्यापक रूप से गिरावट दर्ज की गई। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.15 प्रतिशत की बढ़त के साथ 62.03 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा।

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 3,760.08 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 6,224.89 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

हार्दिक पंड्या की 59 रन की तूफानी पारी से भारत 1-0 से आगे

(एजेन्सी)।
कटक में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में हार्दिक पंड्या ने ऐसी पारी खेली जिसने मैच का रुख पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ दिया। मौजूद जानकारी के अनुसार पंड्या ने महज 28 गेंदों पर नाबाद 59 रन जड़कर भारत को 175/6 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया, जो दक्षिण अफ्रीका के लिए किसी भी हाल में हासिल करना संभव नहीं रहा हैं।

बता दें कि हार्दिक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और उन्होंने मैच के बाद बातचीत में कहा कि विकेट पर उछाल और टर्न दोनों थे, ऐसे में उन्हें अपने अंदरूनी भरोसे पर टिकना पड़ा। पंड्या ने स्पष्ट किया कि यह पारी शक्ति से ज्यादा टाइमिंग की थी, और यही रणनीति उन्हें फायदा पहुंचाती रही हैं।

गौरतलब है कि हार्दिक पिछले कुछ महीनों से फिटनेस को लेकर लगातार एनसीए में मेहनत कर रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले 50 दिनों की सख्त फिजिकल ट्रेनिंग और क्रिकेटिंग ड्रिल्स ने उन्हें मानसिक और तकनीकी दोनों रूप से मजबूत बनाया है, जिसका नतीजा मैदान पर इस शानदार पारी के रूप में देखने को मिला हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि टीम की जरूरत उनके व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से हमेशा ऊपर रहती हैं। हार्दिक ने कहा कि, मुझे हमेशा वही करना पसंद है जो भारत को चाहिए, न कि जो हार्दिक पंड्या चाहता है, यही मानसिकता मुझे खेल में सही फैसले लेने में मदद करती है।

दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर केशव महाराज के खिलाफ अपने अटैक का ज़िक्र करते हुए हार्दिक ने कहा कि मौके को पहचानकर जोखिम उठाना उसी गेमस्मैंशिप का हिस्सा है, जहां गेंद अगर रेंज में हो तो उसे बाउंड्री तक पहुंचाना ही सही विकल्प है। भारत की ओर से तिलक वर्मा और अक्षर पटेल ने भी अहम योगदान दिया, जबकि अफ्रीकी गेंदबाजी में लुंगी एनगिडी सबसे सफल रहे। वहीं दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह बिखरी रही और महज 74 रन पर ढेर हो गई। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि हार्दिक और शिवम दुबे को 1-1 सफलता मिली हैं।

गौरतलब है कि सीरीज पांच मैचों की है और इस जीत के साथ भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है, जिसमें हार्दिक की बैटिंग और नेतृत्व दोनों निर्णायक साबित हुए हैं।

कृतिका कामरा ने गौरव कपूर के साथ अपने रिलेशनशिप को सार्वजनिक किया

(एजेन्सी)। महीनों की अटकलों के बाद अभिनेत्री कृतिका कामरा और टेलीविजन प्रजेंटेटर गौरव कपूर ने अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। कृतिका ने आज सोशल मीडिया पर गौरव के साथ कई तस्वीरें साझा कीं, जिससे प्रशंसकों को वह पुष्टि मिली जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, "नाश्ते के साथ"। लंबे समय इन दोनों कपल की रिलेशनशिप चचाएं चल रही थीं। आज कृतिका ने इन चर्चाओं पर मोहर लगा दी है और गौरव कपूर के साथ अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए कृतिका ने अपने रिश्ते को कंफर्म आखिरकार कर ही दिया है।

प्रियंका चोपड़ा ने जाह्नवी के बेबाक और सच्चे विचारों की जमकर तारीफ़ की

प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में वी द विमेन मंच से जाह्नवी कपूर का प्रभावशाली वीडियो शेयर कर उनके विचारों को खुलकर सराहा। इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस क्लिप को री-पोस्ट करते हुए प्रियंका ने लिखा, बातचीत से शुरुआत होती है, तो मैं भी शामिल होती हूँ। उन्होंने जाह्नवी के बेबाक और सच्चे विचारों की जमकर तारीफ़ की। यह वीडियो बरखा दत्त के प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म वी द विमेन का है, जो देशभर की महिलाओं की आवाज़, उनकी पहचान, महत्वाकांक्षाओं और सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने के लिए जाना जाता है। क्लिप में जाह्नवी कपूर बेहद साफ़गोई से स्त्रीत्व, समाज की अपेक्षाओं और समानता के असली मायनों पर बात करती दिखाई देती हैं। वह बताती हैं कि महिलाओं के अनुभवों को समझना और स्वीकारना कितना ज़रूरी है, बजाय इसके कि समानता को सिर्फ़ एक सतही अवधारणा तक सीमित कर दिया जाए। पीले रंग के आकर्षक आउटफ़िट में नज़र आ रहीं जाह्नवी के स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरे विचार दर्शकों के साथ गहराई से जुड़े और इन्हीं विचारों ने प्रियंका चोपड़ा को उन्हें अपने प्लेटफ़ॉर्म पर साझा करने के लिए प्रेरित किया।

रवि तेजा के साथ स्क्रीन शेयर कर सकती हैं सामंथा रुथ प्रभु

द क्षिण सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु काफी समय से अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। खबरे हैं कि वह निर्देशक राज निदिमोरू के साथ रिश्ते में हैं। इस बीच अभिनेत्री की अगली फिल्म से जुड़ा अपडेट आया है। चर्चा है कि सामंथा पहली बार सुपरस्टार रवि तेजा के साथ स्क्रीन साझा करते हुए नजर आएंगी। दोनों एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक... सामंथा वर्तमान में रवि के साथ एक प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रही हैं। फिल्म का शीर्षक तय नहीं है, लेकिन इसका निर्देशन शिव निर्वाण कर सकते हैं। अगर सबकुछ ठीक रहा तो पहला मौका होगा जब सामंथा और रवि को एक साथ फिल्मी परदे पर देखने का दर्शकों को मौका मिलेगा। अभी तो इस प्रोजेक्ट से संबंधित कोई भी आधिकारिक घोषणा सामंथा या रवि की ओर से नहीं की गई है। फिलहाल तो सामंथा रक्त ब्रह्मांड: द ब्लडी किंगडम में व्यस्त चल रही हैं। यह नेटफ्लिक्स की आगामी वेब सीरीज है, जिसका निर्माण राज और डीके डी 2आर फिल्म्स के तहत कर रहे हैं। इस सीरीज का निर्देशन राही अनिल बर्वे ने किया है। सामंथा के अलावा, इस सीरीज में आदित्य रॉय कपूर, अली फजल, वामिका गब्बी और जयदीप अहलावत नजर आएंगे। दूसरी तरफ, सुपरस्टार रवि अगली फिल्म मास जाथारा में नजर आएंगे इसमें उनके साथ अभिनेत्री श्रीलीला हैं।

मेघना गुलजार की 'दायरा' में पहली बार साथ दिखेंगे करीना और पृथ्वीराज सुकुमारन

निर्देशक मेघना गुलजार इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'दायरा' को लेकर चर्चाओं में हैं। फिल्म की अभी शूटिंग चल रही है। इस बीच अब मेघना गुलजार ने फिल्म के फाइनल शेड्यूल की शूटिंग को लेकर अपडेट दिया है। इस फिल्म में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे।

मेघना गुलजार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने फिल्म के फाइनल शेड्यूल को लेकर जानकारी दी है। मेघना ने जो तस्वीर साझा की है वो किसी कार के अंदर की तस्वीर है। इसमें सीट पर बड़े-बड़े बैग रखे नजर आ रहे हैं। संभवत- इनमें शूटिंग उपकरण हैं। इस तस्वीर को साझा करते हुए मेघना ने कैप्शन में लिखा, 'फाइनल शेड्यूल। यहां हम चले।' इसके साथ हैशटैग में उन्होंने दायरा भी लिखा है।

मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित इस फिल्म को जंगली पिक्चर्स और पेन स्टूडियो ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म में करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन प्रमुख भूमिका में नजर आएंगे। दोनों स्टार्स पहली बार एकसाथ किसी फिल्म में दिखाई देंगे। हालांकि, अभी तक फिल्म को लेकर कोई ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।

'राजी' और 'सैम बहादुर' जैसी फिल्मों का निर्माण कर चुकी हैं मेघना

मेघना गुलजार की गिनती इंडस्ट्री के चुनिंदा निर्देशकों में होती है। वो इससे पहले 'राजी', 'छपाक' और 'सैम बहादुर' जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुकी हैं। तीनों ही फिल्मों को क्रिटिक्स से जबरदस्त सराहना मिली है। वहीं 'छपाक' को छोड़कर बाकी दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही हैं। मेघना की आखिरी फिल्म 'सैम बहादुर' है, जिसमें विक्की कौशल प्रमुख भूमिका में नजर आए हैं। यह फिल्म भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित है।

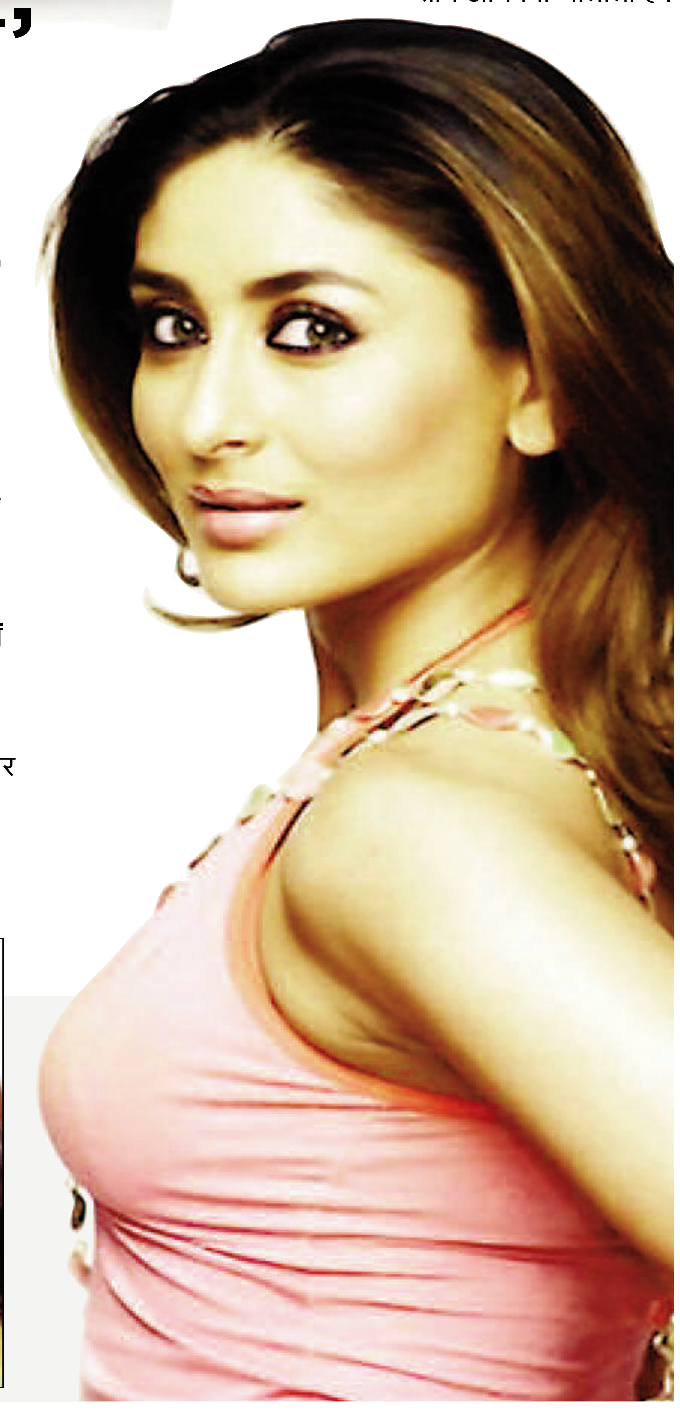

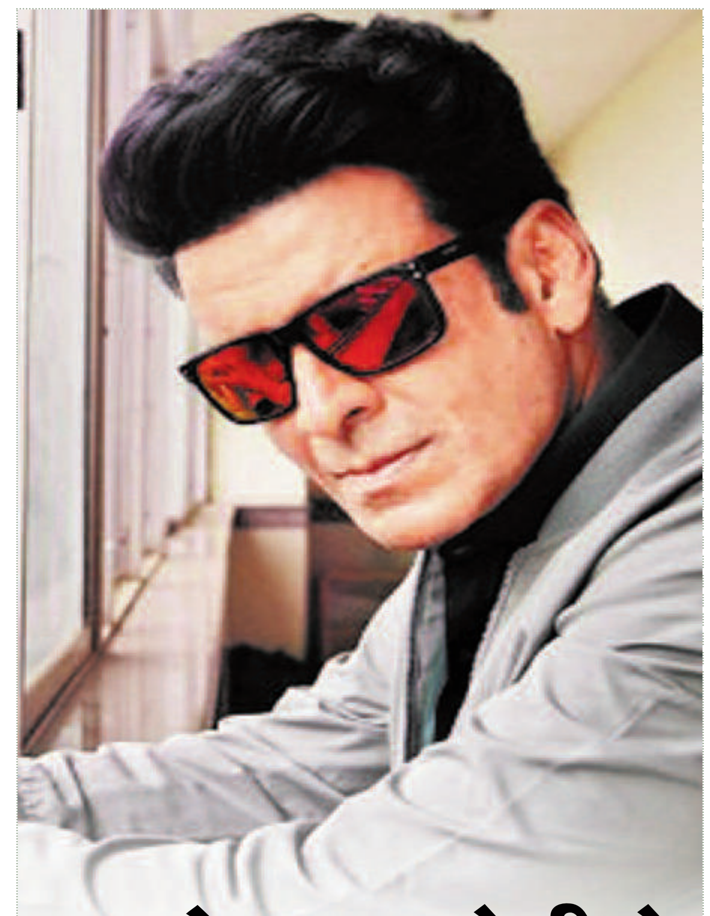

मनोज बाजपेयी ने बॉलीवुड में एक्टर्स की इनसिक्योरिटी के बारे में बात की

एक्टर मनोज बाजपेयी इन दिनों द फैमिली मैन सीजन 3 में अपने अभिनय के लिए तारीफें बटोर रहे हैं। हाल ही में कास्ट ने कुशा कपिला और कॉमेडियन रवि गुप्ता के साथ शो के बारे में कई बातें कीं। बातचीत में मनोज बाजपेयी ने बॉलीवुड में एक्टर्स के बीच मौजूद इनसिक्योरिटी के बारे में खुलकर बात की।

अनिश्चितता में हैं बॉलीवुड के कलाकार

मनोज बाजपेयी ने बॉलीवुड एक्टर्स में अनिश्चितता की भावना के बारे में बात की। उन्होंने कहा, हमारी इंडस्ट्री में, एक्टर्स कभी एक-दूसरे की तारीफ नहीं करेंगे। वे कभी किसी के काम की तारीफ करने के लिए कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि वे बहुत इनसिक्योर होते हैं। मैं अब भी लोगों को काम मांगने के लिए कॉल करता हूं। क्योंकि मैं पैदाइशी संघर्ष करने वाला इंसान हूं।

रो पड़े थे जयदीप

बातचीत में जयदीप अहलावत ने बताया कि मनोज बाजपेयी ने पाताल लोक सीजन 1 में उनके काम की तारीफ की तो वह रो पड़े थे। उन्होंने कहा जब पाताल लोक सीजन 1 रिलीज हुआ था, तो मनोज भाई ने मुझे रात में फोन किया और मुझसे 15-20 मिनट बात की। मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उसके बाद, मैं बहुत रोया। उस समय मनोज बाजपेयी ने जयदीप अहलावत से कहा एक इंस्टिट्यूशन खोलो, और मैं तुम्हारा छात्र बनूंगा।

मनोज और जयदीप साथ में कर चुके काम

द फैमिली मैन 3 से पहले, मनोज बाजपेयी और जयदीप अहलावत ने 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर और चटगांव में साथ काम किया था। द फैमिली मैन के नए सीजन में, मनोज बाजपेयी ने श्रीकांत तिवारी का अपना रोल फिर से निभाया है, जबकि जयदीप अहलावत ने विलेन रुक्मा का रोल किया है।

द फैमिली मैन 3 की कास्ट

द फैमिली मैन 3 के निर्देशक राज एंड डीके हैं। शो में मनोज बाजपेयी, निमरत कौर, अश्लेषा ठाकुर, शारिब हाशमी, प्रियमणि और जयदीप अहलावत अहम रोल में हैं। 21 नवंबर से यह शो अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहा है।

धुरंधर' को लेकर भारत- पाक दोनों में हो रही चर्चा

बॉलीवुड फिल्म निर्माता आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' को लेकर भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में भी काफी चर्चा हो रही है। इसकी वजह है संजय दत्त द्वारा निभाया गया कराची के दिवंगत एसपी चौधरी असलम का किरदार। फिल्म रिलीज से पहले चौधरी असलम की पत्नी नौरीन ने एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने इस किरदार को लेकर अपनी उम्मीदें और नाराजगी दोनों जाहिर की थीं। नौरीन ने बताया कि वह और उनके पति दोनों संजय दत्त के बड़े प्रशंसक रहे हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी असलम 90 के दशक की मशहूर फिल्म 'खलनायक' देखने के बाद संजय दत्त के फैन बन गए थे, जबकि नौरीन पहले से ही उनकी एक्टिंग को पसंद करती थीं। उन्हें भरोसा था कि संजय दत्त उनके पति की पर्सनैलिटी के साथ न्याय करेंगे। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद उनकी भावनाएं आहत हुईं, जहां चौधरी असलम को 卐जिन्न卐 कहकर संबोधित किया गया है। नौरीन के अनुसार यह शब्द बेहद आपत्तिजनक और असम्मानजनक है।

नौरीन ने कहा 卐शैतान से पैदा होने वाले बच्चों को जिन्न कहा जाता है। हम मुस्लिम हैं और ऐसे शब्द हमारे लिए अशोभनीय हैं। यह सिर्फ असलम के लिए ही नहीं बल्कि उनकी मां के लिए भी अपमान है। अगर फिल्म में मेरे पति को गलत तरीके से दिखाया गया है या उनके खिलाफ प्रोपागैंडा किया गया है, तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी।卐 उन्होंने भारतीय फिल्ममेकर्स पर आरोप लगाया कि वे अक्सर पाकिस्तान की खराब छवि दिखाने की कोशिश करते हैं और इसे 卐बड़ी अजीब बात卐 बताया। इंटरव्यू में नौरीन ने यह भी बताया कि चौधरी असलम उनके मामू के बेटे थे और शुरुआत में वह शादी के लिए तैयार नहीं थीं, लेकिन बाद में उनसे गहरा प्यार हो गया। उन्होंने कहा—卐अगर जिंदगी दोबारा मिले, तो खुदा से फिर वही मर्द मांगूंगी चौधरी असलम।卐 उन्होंने यह भी बताया कि असलम हमेशा कहा करते थे कि उन पर फिल्में बनेंगी।

नौरीन का मानना है कि संजय दत्त ने अपना काम एक अभिनेता के रूप में किया है और अगर गलती है तो यह कहानी लिखने वालों की है। उन्होंने कहा कि वह इंटरनेशनल लेवल पर भी कानूनी कार्रवाई करने का हक रखती हैं क्योंकि यह फिल्म दुनिया भर में दिखाई जाती है और इससे आने वाली पीढ़ियों को गलत संदेश जा सकता है। 1963 में जन्मे चौधरी असलम ने सिंध पुलिस में एएसआई के तौर पर नौकरी शुरू की। 2000 में उन्हें ल्यारी टास्क फोर्स का प्रमुख बनाया गया। उन्होंने कई कुख्यात गैंग्स का सफाया किया। 2011 में तालिबान ने उन पर हमला किया, जिसमें वह बच गए, लेकिन 2014 में टीटीपी के एक बड़े बम धमाके में उनकी मौत हो गई। बता दें कि यह फिल्म आजकल बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है और दर्शकों से बेहतरीन प्रतिक्रिया मिल रही है।

हरियाणा की भाजपा सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों से किया सबसे बड़ा विश्वासघात-कुमारी सैलजा

■ हर गरीब को छत देने का वादा भूली सरकार, आज भी देश में करोड़ों परिवार बिना घर के कर रहे है गुजर-बसर

एसबी विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। प्रधानमंत्री ने 2022 तक देश के हर गरीब को छत देने का वादा किया था, लेकिन आज भी करोड़ों परिवार बिना घर के गुजर-बसर कर रहे हैं। हरियाणा भी इससे अलग नहीं है।

मीडिया को जारी बयान में सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हुडा, जिसे कभी नो-प्रॉफिट, नो-लॉस के सिद्धांत पर गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ती दरों पर प्लॉट उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था, उसका स्वरूप सरकार ने पूरी तरह कमजोर कर दिया है। आज जनता को घर देना सरकार की प्राथमिकता नहीं बल्कि प्राइवेट बिल्डरों के लिए खुला मैदान बन गया है।

प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कॉलोनियां काटी जा रही हैं, कहा तो यह जाता है कि इन योजनाओं के माध्यम से गरीबों को प्लॉट दिए जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि छोटे नगरों से लेकर मध्यम शहरों तक 50 लाख से एक करोड़ रुपए तक के प्लॉट बेचे जा रहे हैं। ऐसा महंगा प्लॉट गरीब यहां तक कि मध्यम वर्ग की पहुंच से भी बाहर है। एक गरीब इतना मंहगा प्लॉट खरीदने के बारे में सोच ही नहीं सकता फिर किस मुंह से सरकार गरीबों के हितों की बात कर रही है। सच तो यह है कि प्रदेश सरकार गरीब को अपने घर का सपना दिखाकर उसके साथ मजाक कर उसका उपहास उड़ा रही है।

सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि यह सरकार केवल और केवल प्रोपर्टी डीलर के बारे में सोच रही है, इस सरकार के कार्यकाल में लाइसेंस सस्ते और प्लॉट महंगे होते जा रहे है, सरकार की नीतियों से आम आदमी को कोई राहत नहीं मिल रही है। सांसद ने कहा कि गरीबों के लिए बनाई गई योजनाएं भी अब गरीबों तक नहीं पहुंच रहीं है वे सिर्फ डेवलपर्स की कमाई का साधन बनकर रह गई हैं। सांसद कुमारी सैलजा ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि क्या यही आपका विकास मॉडल है कि गरीब और मिडिल क्लास शहरों से बाहर धकेल दिए जाएं और प्राइवेट डेवलपर्स की बल्ले-बल्ले हो? क्या सरकार गरीब को घर देने की नीति छोड़ चुकी है? सांसद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब और मध्यम वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ती आई है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम फिर से ऐसी व्यवस्था लाएंगे जिसमें हर परिवार को सम्मानजनक दरों पर घर और प्लॉट मिलें, न कि सिर्फ अमीरों और बिल्डरों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियां।

राजस्व कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं-उत्तम सिंह

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि राजस्व संबंधी कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी व कर्मचारी जनहित में पूरी तत्परता के साथ दायित्वों का निर्वहन करें ताकि नागरिकों को समय पर सेवाएं मिल सकें। सिविल कोर्ट में लंबित मामलों, रजिस्ट्री और इंतकाल के लंबित कार्यों को भी शीघ्रता से निपटाया जाए। इसके साथ ही जमाबंदी से संबंधित लंबित मामलों को 15 दिन से ज्यादा लंबित न रखा जाए।

उपायुक्त उत्तम सिंह आज लघु सचिवालय सभागार में आयोजित राजस्व विभाग की मासिक बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट में लंबित मामलों के साथ-साथ राजस्व से संबंधित मामलों का निपटारा तय समय सीमा में किया जाए।उन्होंने निर्देश दिए कि तहसील कार्यालयों में साफ-सफाई की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही तहसील कर्मचारियों द्वारा औपचारिक पोशाक (फॉर्मल) पहनना सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिए कि 47 ए के लंबित मामलों को तेजी से निपटान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही स्टांप डयूटी, कोर्ट केस, रिकवरी सर्टिफिकेट आदि से संबंधित सरकारी बकाया राशि की वसूली के कार्य में भी तेजी लाई जाए। उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लें और प्राथमिकता से उनका निपटारा करें। किसी भी मामले में अनावश्यक देरी व उसे जानबूझकर लटकाए रखना स्वीकार्य नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति दोबारा उनके पास शिकायत लेकर नहीं आना चाहिए।

बैठक में घरौंडा एसडीएम राजेश सोनी, इंद्री के एसडीएम अशोक मुंजाल, असंध के एसडीएम राहुल, नीलोखेड़ी के एसडीएम अशोक कुमार, डीआरओ मनीष यादव, डीडीपीओ कंचनलता सहित तहसीलदार व नायब तहसीलदार मौजूद रहे।

कडली कैटरपिलर स्कूल का वार्षिकोत्सव धूमधाम से संपन्न

एसबी संवाददाता

वाराणसी। हर वर्ष की भाति कडली कैटरपिलर स्कूल का 16वां वार्षिकोत्सव बुधवार को होटल मादिन कैंटोनमेंट में मनाया गया। हमारे चेयरमैन संदीप किशोर चौरसिया ने मुख्य अतिथि ऐ. सी. पी. विदुष सक्सेना और विशिष्ट अतिथि अंकुर चढ़ा (जनरल मैनेजर ऑफ दैनिक जागरण) को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करके कार्यकम की शुरूवात की और बच्चो को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

इस वर्ष कार्यकम का विषय रहा "डिजिटल आरम्भ" जो नई शुरूवात और आधुनिक शिक्षा की ओर हमारे कदम का प्रतिक है। डिजिटल आरम्भ मात्र एक शीर्षक नहीं, बल्कि भविष्य के लिए हमारे बच्चो को तकनिकी रूप से सशक्त बनाने का संकल्प है।

इस कार्यकम में मुख्य रूप से जगत किशोर चौरसिया, श्रीमती लक्ष्मी चौरसिया, संदीप किशोर चौरसिया, श्रीमती विनती किशोर चौरसिया और समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे।

पूंडरी विधायक सहित हरियाणा के 40 विधायकों ने किया संसद भवन का दौरा

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। हरियाणा विधानसभा के 40 विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को देश की राजधानी में पुराने और नए संसद भवन का भ्रमण किया, जो उनके लिए एक अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक अनुभव रहा। इस प्रतिनिधिमंडल में पूंडरी विधायक सतपाल जांबा भी शामिल रहे। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने की।

विधायक सतपाल जांबा ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि हमने लोकतंत्र के इस सर्वोच्च मंदिर की भव्यता और गरिमा को करीब से देखा। विशेष रूप से नए संसद भवन की आधुनिक संरचना और भारतीय संस्कृति पर आधारित उत्कृष्ट कलाकृतियों का अवलोकन किया। भ्रमण के दौरान, संसद सत्र के तहत लोकसभा की कार्यवाही को देखने का अवसर मिला। इस दौरान हमने देश के नीति-निर्माण की प्रक्रिया और सदन के अंदर होने वाली महत्वपूर्ण चर्चाओं को प्रत्यक्ष रूप से समझा।

इसके अलावा संसद परिसर स्थित आर्ट गैलरी और लाइब्रेरी का भी भ्रमण किया। आर्ट गैलरी में देश के इतिहास और संवैधानिक विकास से जुड़ी कलाकृतियों ने उनका ध्यान आकर्षित किया, जबकि लाइब्रेरी में उन्होंने भारत के विधायी और राजनीतिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण साहित्य और दस्तावेजों को देखा। इसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन से भी शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात उनके लिए एक यादगार क्षण रहा, जहाँ उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्तित्व से सीधे बातचीत करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह बहुत अच्छा अनुभव रहा, जिसके लिए मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी तथा हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। उनकी पहल पर आयोजित इस दौरे ने उन्हें भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली और संसदीय प्रक्रियाओं की गहन समझ प्रदान की है। यह अनुभव भविष्य में उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए बेहतर कार्य करने में सहायक होगा।

कैथल पुलिस का 'नशा मुक्त हरियाणा' अभियान जारी, कलायत व कैथल शहर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। हरियाणा पुलिस महानिदेशक ओ.पी. सिंह के आदेशानुसार नशा मुक्त हरियाणा मुहिम के तहत कैथल जिला पुलिस द्वारा समाज को नशे से मुक्त करने के उद्देश्य से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। एसपी उपासना के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीमें गांवों, कस्बों और शहरी क्षेत्रों में पहुंचकर आमजन को नशे के दुष्परिणामों से अवगत करवाते हुए नशा छोड़ने तथा नशा न करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार को डीएसपी कुलदीप बेनीवाल की अगुवाई में एसआई कर्मबीर, एचसी सुनील कुमार, महिला सिपाही किस्मत व सोनिया, तथा एसपीओ राजपाल, प्रदीप कुमार और जसविंदर की संयुक्त टीम ने कलायत क्षेत्र तथा कैथल शहर में विशेष जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अभियान के दौरान पुलिस टीम को कलायत क्षेत्र में कई सुनसान स्थानों पर कुछ नशेड़ी नशा करते हुए मिले। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें थाना कलायत ले जाकर काउंसलिंग करवाई। काउंसलिंग के दौरान उन्हें नशे के दुष्परिणामों, इससे होने वाले स्वास्थ्य नुकसान तथा पारिवारिक-सामाजिक प्रभावों के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया गया। इसके साथ ही पुलिस द्वारा उन्हें नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करते हुए इलाज की सलाह भी दी गई। टीम द्वारा आमजन को जानकारी दी गई की नशा न केवल व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य खराब करता है, बल्कि उसके परिवार व समाज के लिए भी गंभीर चिंता का कारण बन जाता है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और किसी भी संदिग्ध नशा तस्करी गतिविधि की सूचना पुलिस को देने की अपील की। एसपी उपासना ने कहा कि जिला कैथल पुलिस नशा तस्करी पर सख्त कार्रवाई और व्यापक जागरूकता दोनों माध्यमों से समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। उन्होंने बताया कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग इस मुहिम से जुड़कर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें।

हरियाणा सरकार की ओर से जिले को जल्द मिलेगा मेडिकल कॉलेज का तोहफा

■ 935 करोड़ की लागत से गांव सांपन खेड़ी में बन रहा भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा जिले के गांव सांपन खेड़ी में बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जून 2026 में पूरा होने की संभावनाएं हैं। भगवान परशुराम राजकीय मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसका करीब 74 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसके शुरू हो जाने से कैथल सहित आस-पास के जिलों के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में बड़ा लाभ होगा। इस समय जरूरत होने पर जिला अस्पताल से मरीजों को चंडीगढ़, रोहतक पीजीआई या फिर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेफर किया जाता है।

कैथल जिले के विकास को एक नई दिशा देते हुए करीब 935 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से यह मेडिकल कॉलेज बन रहा है। निर्माण कार्य में कई-कई मंजिला भवन बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके बन जाने से न केवल कैथल जिले के स्वास्थ्य सेवाओं का कायाकल्प होगा, बल्कि छात्रों के लिए 100 एमबीबीएस सीटों पर डॉक्टरों की पढ़ाई का रास्ता भी खुलेगा। यह परियोजना

निर्माणाधीन भगवान परशुराम राजकीय मेडिकल कॉलेज कैथल। (छाया: एसबी)

हरियाणा सरकार की प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं और मेडिकल शिक्षा को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण की घोषणा की थी। जिसे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी गहन रूचि लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। उनके निदेर्शानुसार मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। यह मेडिकल कॉलेज कैथल-करनाल रोड पर ग्राम पंचायत सांपन खेड़ी की 20 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना पर सितंबर 2023 में संबंधित एजेंसी द्वारा कार्य शुरू किया गया था। परियोजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से लैस कई इमारते शामिल हैं। मुख्य रूप से 530 बिस्तरों वाला अस्पताल भवन बनेगा, जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर तथा सात मंजिले होंगी। इसी प्रकार मेडिकल कॉलेज भवन में 100 एमबीबीएस सीटों के साथ, परीक्षा हाल सहित अन्य सुविधाएं होंगी। इसमें 350 व 250 क्षमता के साथ क्रमशः लड़कों एवं लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाया जा रहा है। इसमें डाइनिंग/किचन की सारी सुविधाएं मौजूद रहेंगी।

वहीं जूनियर एवं सीनियर रेजिडेंट और क्लास 1 व 2 अधिकारियों के लिए आवास ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल उपकरण, सामान्य फर्नीचर और साइट का विकास, बाहरी सेवाओं और अन्य संबंधित कार्यों को भी शामिल किया गया है। परियोजना के लिए आवश्यक सभी वैधानिक मंजूरियां प्राप्त की जा चुकी हैं, जैसे बिल्डिंग प्लान की मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी, सीएलयू तथा प्री-फायर एनओसी आदि।

> एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद भगवान परशुराम राजकीय मेडिकल कॉलेज कैथल और आस-पास के क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलेगा। यह न केवल बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा, बल्कि युवाओं को 100 एमबीबीएस सीटों के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करेगा।
> -अपराजिता, डीसी, कैथल।

उपायुक्त कैथल अपराजिता

मानवाधिकार जागरूकता दिवस के समापन समारोह को बड़े धूम धाम से मनाया गया

संजना भारती संवाददाता

मोतिहारी। सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद अजहर हुसैन अंसारी के द्वारा मानवाधिकार जागरूकता दिवस के समापन समारोह को मोतिहारी के उर्दू लाइब्रेरी में बड़े धूम धाम से मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता भरावदयाल सिंह, मंच संचालन प्राचार्य मदन कुमार ने किया। मुख्य अतिथि पद से अपने संबोधन में डिग्री कॉलेज भरौलिया मोतिहारी के अध्यक्ष तथा भारत स्काउट और गाइड के जिला मुख्य आयुक्त रत्नेश्वरी शर्मा ने बताया कि अधिकार और कर्तव्य एक सीक्का के दो पहलू हैं। मानवाधिकार के हनन की लड़ाई सब को लड़ना चाहिए क्योंकि बिना लड़े कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। गांधी जी ने लड़ाई का सुगम मार्ग अवज्ञा बताया था।

श्री शर्मा ने मानवाधिकार की रक्षा के लिए जागरूक तथा संघर्षशील रहने का आह्वान किया। अंत में आयोजक मोहमद अजहर हुसैन अंसारी ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

संजना भारती ब्यूरो प्रमुख इंतजार हुसैन

बदायूँ। प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में अधिकारियों के साथ विकास व कानून व्यवस्था आदि की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को गंभीरतापूर्वक व निष्ठा से कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित भारत बन जाएगा तथा उत्तर प्रदेश भी विकसित उत्तर प्रदेश होगा।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस विभाग की शिकायत प्राप्त हो उसकी जांच के आदेश उसी अधिकारी को न दिए जाएं। उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस व थाना समाधान दिवस आदि पर प्राप्त शिकायतों का गंभीरतापूर्वक निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निस्तारण व समाधान नहीं किया जा सकता हो। उन्होंने शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता व रैंकिंग की स्थिति की जानकारी लेते हुए शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता व समयबद्धता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चकमार्ग पर अवैध कब्जे व सरकारी जमीनों पर कब्जे की शिकायतें लखनऊ तक आती हैं इसलिए अधिकारी शिकायतों को गंभीरतापूर्वक लें। उन्होंने कहा कि चकमार्ग पर अवैध कब्जे की शिकायतों के लिए विशेष अभियान चलाकर इसका निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरो को जगमग किया जाए यह सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने सीमांकन कराने के आवेदनों की जानकारी ली। जिस पर जिलाधिकारी ने बताया कि 90 दिन से पुराना कोई मामला लंबित नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के मामलों का निस्तारण पूरी गंभीरता से किया जाए। उपमुख्यमंत्री ने धान खरीद की स्थिति की जानकारी लेते हुए क्रय केन्द्रों का औचक निरीक्षण कराए जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 37000 मेट्रिक टन का लक्ष्य मिला है। जोकि बरेली मंडल में जनपद को सबसे कम लक्ष्य मिला है। डीएम ने बताया कि लक्ष्य पूर्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में इस्लामिया इण्टर कॉलेज चैंपियन

संजना भारती ब्यूरो प्रमुख इंतजार हुसैन

बदायूँ। बुधवार को पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्पोर्ट्स स्टेडियम बहेड़ी में आयोजित जनपद स्तरीय जूनियर वर्ग की क्रिकेट प्रतियोगिता के क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में फाइनल में हाफिज सिद्दीक इस्लामिया इण्टर कॉलेज बदायूं की टीम ने श्रीकृष्ण इण्टर कॉलेज की टीम को हराकर चैंपियनशिप हासिल की। जिस पर समस्त विद्यालय परिवार में हर्ष की लहर दौड़ गई तथा प्रबंधक खिसाल उद्दीन एवं प्रधानाचार्य अब्दुल सुबूर खां, क्रीड़ा प्रभारी एवं कोच मोहम्मद अजीम एवं जहीर खां द्वारा समस्त विजयी छात्रों को बधाई दी गई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं दी गयीं।

आवश्यक सूचना

तेजी से बढते राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र, **'संजना भारती'** को चंडीगढ़, पंचकुला सहित पूरा हरियाणा, पंजाब में जिला स्तर, तहसील स्तर, खंड स्तर पर पत्रकार/कोर्सपोंडेट/ प्रतिनिधि, जिला प्रभारी की जरूरत है।
संपर्क करें: 9871221635

ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन तहत 3 मामलों में 3 आरोपियों के कब्जे से 52.5 बोतल हथकढी शराब तथा 110 लीटर लाहण बरामद

राजौंद पुलिस टीम ने गांव मंडवाल से अवैध शराब बरामद की

एसबी संवाददाता

कैथल। दिसंबर माह में डीजीपी ओपी सिंह के निदेर्शानुसार तथा एसपी उपासना के कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन तहत अवैध शराब का धंधा करने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग 3 मामलों में 3 आरोपियों के कब्जे से 52.5 बोतल हथकढी शराब तथा 110 लीटर लाहण बरामद किया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि थाना राजौंद पुलिस की महिला मुख्य सिपाही सुमन रानी व एचसी अजय कुमार कि टीम द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर मंडवाल निवासी निशान सिंह के मकान पर दबिश देकर संदिग्ध निशान सिंह को काबू किया गया। जांच दौरान आरोपी के कब्जे से 2 प्लास्टिक कैनियों से 35 बोतल हथकढी शराब बरामद हुई। दूसरे मामले में थाना तितरम पुलिस की महिला मुख्य सिपाही रेनु व एएसआई राममेहर की टीम द्वारा हरसौला निवासी राजेंद्र को उसके मकान पर दबिश देकर काबु कर लिया गया। आरोपी अवैध शराब भट्टी चलाकर शराब तैयार कर रहा था। जांच दौरान आरोपी के कब्जे से चलती भट्टी सहित 110 लीटर लाहण, 1 बोतल शराब तथा भट्टी चलाने में प्रयुक्त अन्य उपकरण बरामद हुए। एक अन्य मामले में एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ के एएसआई लखविंद्र सिंह व एएसआई करनैल सिंह की टीम द्वारा पापसर निवासी राजकुमार को उसके मकान से 16.5 बोतल हथकढी शराब सहित काबू किया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज करके पुलिस द्वारा नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।